

the inter-state angle involved, consultation with Orissa Government was considered necessary before the project could be accepted for implementation.

(b) The Scheme envisages the installation of 240 MW of generating capacity comprising three units of 80 MW each.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The Scheme can be cleared for implementation after the Government of Orissa gives its concurrence.]

— — —

12.00 Noon

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI V.B. RAJU)
in the Chair]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RECOMMENDATION OF AGRICULTURAL
PRICES COMMISSION FOR LOWERING THE
PROCUREMENT PRICE OF WHEAT AND
REPORTED DEMONSTRATIONS BY FARMERS
IN PUNJAB AND OTHER PARTS OF THE
COUNTRY AGAINST THE RECOMMENDATION

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : श्रीमन्,
मैं आपकी आज्ञा से गेहूँ के बसूली मूल्य कम
करने के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफा-
रिश और आयोग की इस सिफारिश के
प्रति विरोध प्रकट करने के लिए पंजाब तथा
देश के अन्य भागों में कृषकों द्वारा प्रदर्शन के
समाचार की और कृषि मंत्री का ध्यान
दिलाता हूँ।

THE MINISTER OF AGRICULTURE
(SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED):
Sir, the Agricultural Prices Commission in
their Report on 'price policy for rabi
foodgrains for 1972-73 season' have
recommended that 'the procurement prices
of wheat be fixed uniformly for all the
States at Rs. 66 per quintal for the

indigenous Red, and Rs. 72 per quintal for
the indigenous Common white and
different Mexican varieties.' During the
last year the procurement prices of Red
(indigenous) were fixed between Rs. 71 and
Rs. 74 per quintal and the price of all
other varieties at Rs. 76 per quintal.

Government have seen press Reports
regarding demonstrations by the farmers in
protest against the recommendation of the
Commission. Government have also seen
reports in press regarding various views
expressed in favour and against the views
of the Commission. The recommendation
of the Commission is under consideration
of the Government and a final decision will
be taken only after considering the views of
the Hon. Members and the Chief
Ministers of States who are meeting in a
Conference on the 13th and 14th of
April.

The Honourable House will appreciate
that the policy of price support has been
adopted by Government, to ensure that
the producer gets a remunerative price, the
consumer gets foodgrains at a reasonable
prices and the present trend of production
is sustained. Government have especially
created the Food Corporation of India a
public sector agency to undertake massive
marketing operation, to achieve these
objectives of the price policy. In deciding
the procurement price of wheat for the
coming marketing season Government will
keep in view the objectives of the price
policy, and that the interest of the producer
and the consumer are fully protected.

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : श्रीमन्,
हिन्दुस्तान के किसान वास्तव में बर्बाद के
पात्र हैं कि उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर
बढ़ने के लिए एक मजबूत कदम उठाने में
सहायता दी है। लेकिन यह बहुत बड़ी
बिडम्बना है कि जहाँ किसान को उसके
लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिये और
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, वहाँ कृषि

मूल्य आयोग की इस सिफारिश को अगर स्वीकार किया गया तो उसको पुरस्कृत करने की बजाए अपने परिश्रम के लिए दंडित किया जायेगा और इस कारण, मैं मानता हूँ, यह सिफारिश सर्वथा अन्यायपूर्ण है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। मैं उम्मीद करता था कि सरकार भी इस अवसर पर अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं हमको बताएंगी।

श्रीमन्, पिछले कई वर्षों से कृषि मूल्य आयोग यह सिफारिश करता आया है कि वसूली मूल्य घटाया जाए, लेकिन हर साल जो भी मुख्य मन्त्रियों की कान्फरेन्स होती रही है उसमें प्रति वर्ष इसका विरोध किया गया और कहा गया है कि आज भी जो मूल्य है वे लाभकारी मूल्य नहीं हैं। तो मैं सरकार से कुछ बातें जानना चाहूँगा। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सिफारिश की घोषणा होते ही देश भर के सभी ग्रामवासियों में एक बहुत बड़ी बेचैनी फैली हुई है कि यह निर्णय या यह सिफारिश केवल कोई गिने-चुने बड़े किसानों को प्रभावित नहीं करती परन्तु सम्पूर्ण किसानों को प्रभावित करती है, खास कर के छोटे किसान इसके कारण बहुत त्रस्त हैं। न केवल छोटे किसान बल्कि मैं समझता हूँ, कृषि पर आधारित जो भी लोग हैं, जैसे खेतिहर मजदूर, उनका भी पारिश्रमिक इसके कारण घट जाएगा और इसके कारण वे भी परेशान हैं, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? मैं इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उपभोक्ता पर भार कम करने के लिए यह सिफारिश की गई है। यह सर्वथा सम्भव है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बाद भी उपभोक्ता की कीमत में कोई भी बढ़ोत्तरी न हो, और इस सम्बन्ध में मैं

सरकार से जानना चाहूँगा कि जब इस साल इस बात की सम्भावना है कि हमारी गेहूं की पैदायश करीब 25 लाख टन और बढ़ जाए, और जिसके कारण हमको आयात न करना पड़े, तो क्या यह सही नहीं है कि आयात बन्द करने के कारण लगभग 99 करोड़ रु० जो हमको दुलाई के देने पड़ते थे, ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज, शिपिंग चार्ज, उसकी हमको बचत हो जाएगी? और जब अग्रिकलचर प्राइस कमिशन ने कहा है कि 120 करोड़ रुपये के मूल्य का बोझ सरकार का बढ़ जायेगा और इस कारण हम को प्रोक्योरमेंट प्राइस कम करनी चाहिए। इस तरह से 120 करोड़ रुपये में से 99 करोड़ रुपया बच जायेगा जो दुलाई के चार्ज है। मैं कृषि मन्त्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि पंजाब कृषि विद्यालय के आंकलन के अनुसार उत्पादन खर्च जो किसान को आता है वह 82 रु० प्रति क्विन्टल गेहूं का आता है और अग्रिकलचर प्राइस कमिशन में खर्च कितना होता है, लागत कितनी होती है किसान की, इसका अन्दाजा उसने नहीं लगाया है। लेकिन यह कहा गया है कि आज जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसको कम करने से किसान को लाभ हो सकता है। इस संबंध में मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा और विशेषकर इस कारण भी कि जब पंजाब केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत था, क्या यह सही नहीं है कि उस समय जब कि वहां पर कोई शासन नहीं था, उस समय वहां पर जो डेवलपमेंट कमिशनर थे, उन्होंने स्वयं रिकमेंड किया था अग्रिकलचर प्राइस कमिशन को कि वसूली मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस को 76 रु० से बढ़ाकर 80 रु० 76 पैसे पर क्विन्टल कर दिया जाय। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो यह रिकमेंडेशन किया वह बगैर सोच समझे नहीं किया होगा। अगर

[श्री लाल आडवाणी]

उन्होंने इस प्रकार का रिकमेडेशन किया तो उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सलाह करके किया होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है या नहीं ?

मैं समझता हूँ कि सवाल साफ है। श्रीमती ग्रेवाल जो उस समय डेवलपमेंट कमिश्नर थी और पंजाब का शासन उस समय केन्द्र के अधीन था, वहाँ पर प्रेसीडेंट रूल था, तो उन्होंने जो यह रिकमेडेशन कि 76 रु० जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वह इनएडीक्वेट है और उसके स्थान पर 80 रु० 76 पैसा प्रति विवन्टल होना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : I think it will be sufficient. You have put many questions.

SHRI LAL K. ADVANI : I am not making a speech. I am just finishing

मैं जानना चाहूँगा कि अगर मानो सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है और देश भर में जिस प्रकार का विरोध है, जो किसानों की भावनाएँ हैं, उस भावना को ध्यान में रख कर इस सिफारिश को मजूर करेगी ? अगर यह सिफारिश स्वीकार की जाती है, तो सरकार के सामने ऐसी कौनसी योजना है जिसके परिणाम स्वरूप जो साधारण किसान है उस पर इसका भार न पड़े और अगर किसी को इसके कारण कुछ भार वहन करना पड़ता है तो जो सम्पन्न किसान है और जिन सम्पन्न किसानों के नाम पर इस सिफारिश को उचित माना जा रहा है। यदि सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है जैसी कि माग हो रही है, तो उस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के ऊपर भार न पड़े क्योंकि गेहूँ की कीमत बाजार में बढ़ जायेगी, इस दृष्टि से सरकार

ने उस हालत का सामना करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Every year the decisions are taken by the Government after taking into consideration the recommendations made by the Agricultural Prices Commission and after they are discussed by the Chief Ministers at a conference and after the views of the honourable Members from this House and the Lok Sabha have also been ascertained. Then the Government takes a decision and the same procedure will be followed so far as this year is concerned. And we shall take a decision after the views have been ascertained at various levels. Now, it is true that there has been a demonstration not only at one place, but in a number of places in Punjab, against the reduction in prices recommended by the Agricultural Prices Commission. There has been some demonstration in Haryana also, at Sonapat. There are press reports of such demonstrations in other places also. It is a fact. So far as the price is concerned, that has to take into account the various factors and all those factors are kept in mind. The other day we had the benefit of the advice and opinions given by the members of the Consultative Committee. I hope advice and opinions will also be given by the Chief Ministers at their Conference which is going to be held on the 13th of this month. After that a decision will be taken.

श्री लाल आडवाणी : पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हिसाब से 82 रुपए उत्पादन मूल्य आता है।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : It is true that certain attempt has been made by the agricultural universities and also by the Economic and Statistical Department of the Punjab Government to assess the cost of production at a little over Rs. 80 per quintal. These facts were before the Agricultural Prices Commission and they

have taken that into consideration for fixing the price.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, जो कृषि मूल्य आयोग बनता है उसकी हर बार ऐसी सिफारिश आती है जिन पर सारे देश के किसानों को आपत्ति होती है और अन्त में सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। तो क्या हम यह समझें कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बैठाया जाता है वह ऐसे निकम्मे लोगों का बैठाया जाता है जो इस देश के किसानों से कतई हमदर्दी नहीं रखते और न उनको इस बात की जानकारी होती है कि जो कृषि उत्पादन होता है उसमें क्या व्यय होता है और क्या मूल्य होना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग ने तीन आधार बताए हैं जिनके ऊपर उन्होंने मूल्य निर्धारित किया है (1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ के वर्तमान खरीदारी और बिक्री मूल्य पर गेहूँ की मांग उसकी सम्पूर्ति की अपेक्षा कम है, (2) वर्तमान खरीदारी भाव रखने में केन्द्रीय सरकार को करीब 132 करोड़ रुपए की सहायता देनी पड़ेगी तथा (3) गेहूँ का बाजार मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा कम रहा है। माननीय मंत्री जी क्या बतलायेंगे कि क्या इसी प्रकार से किसी भी उद्योग धन्धे से उत्पन्न वस्तु का मूल्य आज तक इस देश में निर्धारित किया गया है जिस प्रकार से कृषि मूल्य आयोग किसानों का गला काट कर निर्धारित कर रहा है? मैं समझता हूँ कि यह किसानों की हमदर्दी कतई नहीं है। क्या कोई भी प्रदेश की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने कभी भी कृषि मूल्य आयोग के इस मूल्य का समर्थन किया हो। हमें प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रतिवेदन मिला है ऊसमें साफ तौर से कहा गया है कि गेहूँ का जो खरीदारी मूल्य रखा गया है उसमें मानसून के बाद 2 रुपए प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी जाय

ताकि एक बार में बाजार में इतना अधिक गेहूँ न आ सके कि उसकी खरीदारी पर असर पड़े और किसानों को लूटा जा सके। मैं एक स्पष्टीकरण और चाहूँगा कि क्या सरकार की यह नीति हो रही है कि धीरे धीरे गेहूँ की खरीदारी का मूल्य कम किया जाय और धीरे धीरे जो बिक्री का मूल्य है वह बढ़ाया जाय gradual lowering of procurement prices and phased programme of raising the issue prices? इस तरह का अगर विचार है तो हम समझते हैं कि यह भी किसानों के ऊपर घोर अत्याचार है। क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि मूल्य निर्धारित करते समय आयोग उत्पादन व्यय का ध्यान रखेगा और दूसरे आयोग का पुनर्गठन किया जाय, उसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, आयोग की प्रक्रिया ऐसी निर्धारित हो कि किसानों के प्रतिनिधियों की बातें सुन कर तब वह सरकार को सलाह दे? अगर ऐसा करना सम्भव न हो तो क्या सरकार इस आयोग को भविष्य में खत्म कर देगी और स्वयं संसद की, राज्य सरकारों की, अपनी सलाहकार समितियों की राय के ऊपर मूल्य निर्धारित करने की कृपा करेगी?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

So far as the motive attributed to the Agricultural Prices Commission is concerned, I do not agree with the hon. Member. They have taken into consideration the various factors and various materials placed before them and they have come to a certain decision after that. They have given reasons for their decision. But it is not a fact to say that the Government will accept all the reasons which they have given. Government will take into consideration all these facts. What they have decided is their own independent decision.

Now, Sir, so far as the prices are concerned, we shall consider what has been the effect on prices, you see, during the

[Shri Fakhruddin Ali Ahmed]

last two or three years But, one thing I would like to state before this House. So far as the enunciation of our policy is concerned, we will take into consideration the fact that the price fixed is such that it is remunerative to the producer, that it is reasonable so far as the consumer is concerned and that it will not stop the increase in the production of wheat

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V B RAJU): Yes, Mr. Jain.

श्री श्याम लाल यादव एक बात रह गयी। अनाज का जो उत्पादन मूल्य है, जो शुल्क है उसको भी क्या आप ध्यान में रखेंगे मूल्य तय करते वक्त ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : That will be taken into consideration.

श्री ए० पी० जैन (उत्तर प्रदेश) पहला सवाल तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप के मूल्य आयोग के जो मेबर हैं उनकी क्या योग्यता है ? और क्या उनको कोई ज्ञान है कि जिसके आधार पर वह इसके उपयुक्त समझे जाय कि वे इन प्राइसेज का निश्चय कर सकें।

(Interruption)

दूसरे यह कि उनमें कोई किसान है या नहीं। (Interruption) और वे कभी किसानों से कोई मशविरा करते हैं या नहीं ?

अब जितने खेती के इनपुट्स हैं उन पर पहले तो हमारे महामान्य मोरार जी देसाई ने 10 परसेंट का फटलाइजर पर टैकम लगा दिया था। पार साल टैकम लगा दिया गया ट्रैक्टर के ऊपर, इस बार लगा दिया गया पम्प के ऊपर और जो यह फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी 10 परसेंट से 15 परसेंट कर दी गयी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : चुनाव के बाद लगा है पहले नहीं।

श्री ए० पी० जैन : और इस लिए जहाँ तक इसके इनपुट्स की कीमत है वह तो बढ़ गयी लेकिन जनाब के दरबार में गेहूँ के दाम गिरने चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या फेक्टर्स उन्होंने लिये और जब इनपुट्स की कीमत बढ़ी तो गेहूँ के दाम क्यों गिरने नहीं चाहिए, इसकी वजह क्या है ? और आपकी प्राइस सपोर्ट के मायने हैं कि किसानों को और फायदा हो। या आप की प्राइस सपोर्ट के मायने केवल यह है कि प्राइसेज केवल डिमांड और सप्लाई के ऊपर फिक्स की जाय, जैसा कि श्यामलाल यादव जी ने तीन बातें पढ़ कर सुनायी इस विषय में, वह बात सही मालूम होती है।

आखिरी सवाल मेरा यह है कि पार साल कीमत जो थी वह 76 रुपए फी क्विन्टल थी और यह 1969 में गालिबन मुकर्रर हुई थी। आज जो रुपये का मूल्य है अगर उस से कीमत लगायी जाय, सन् 1969 की प्राइसेज के ऊपर अगर आज के रुपए का मूल्यांकन किया जाय तो वह प्राइस 67 रुपए बैठती है। यह आपकी मिनिस्ट्री की एक्सरसाइज है, मेरी नहीं। यानी 76 रु० क्विन्टल पर गेहूँ बेचे तो 1969 की जो कीमते हैं उसके हिसाब से उसको 67 रुपए मिलेंगे, यानी 9 रुपए तो वह कम हो गये, फिर जो इनपुट्स पर आपने दाम बढ़ा दिया वह अलग। तो क्या आप इस तरह से किसान को बिलकुल जान से मारना चाहते हैं यह मैं आप से पूछना चाहता हूँ।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED . Sir, it is true that there is no agriculturist so far as the membership of the Commission is concerned. But, Sir, the Agricultural Prices Commission takes into consideration the views of the agriculturists.

There is a panel of farmers who are consulted and I think. . .

(Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उन्होंने पूछा है कि मेम्बर्स कौन-कौन हैं और उनकी क्वालीफिकेशन्स क्या है ?

श्री श्याम लाल यादव : मेम्बर्स पार्लिया-मेंट को कभी कमीशन ने इन्वाइट किया ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : They are being consulted before they come to final decisions and make their recommendations and it is also not a fact that they do not take into consideration all the other facts. In fact, the fact was placed before them that as compared to the last year's prices the cost of production has increased by about Rs. 4 per quintal on account of increase in the prices of lubricants, machinery and also increase in wages, etc. I mean this fact was taken into consideration. But, we are of the opinion that there was sufficient scope even then to give remunerative prices lower than what was fixed for the last year.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Yes, Mr. Misra.

श्री ए० पी० जैन : आखिरी हिस्से का जवाब बिलकुल नहीं मिला। इस वक्त रुपए के दाम को देखते हुए 69 के हिसाब से 67 रुपए दाम बैठता है।

This is your exercise, not mine.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED . I have already said that the opinion of the Prices Commission is that even after taking into consideration all these facts the prices given or recommended by them will be remunerative to the cultivator.

SHRI A. P. JAIN : I am asking whether on the basis of 1969 prices, these are remunerative. He can either accept it or deny it.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED . No assessment has been made. . .

(Interruption)

SHRI A. P. JAIN : It is a blunder. . .

(Interruptions)

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, अभी माननीय जैन साहब ने जो सवाल किया उसी को दूसरे ढंग से माननीय मन्त्री जी सोचें कि 1969 ई० में जो प्राइस थी और आज जो प्राइस है तो क्या यह बात सही है कि जब 67 रुपए की कीमत आपने देने को कहा था तो आज की प्राइसेज में उसे दें तो कम से कम 86 रुपए देना होगा। क्या यह सही है या नहीं है। 1969 को देखें, तब अगर 67 होता है तो आज की प्राइसेज से 86 होना चाहिए या नहीं और क्यों माननीय मन्त्री जी या एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन जो बना हुआ है वह इसे नहीं सोचता। एक तो मैं बिलकुल ताईद इस बात की करता हूँ, जो आवाज उठाई जाती है और बराबर उठाई गई है; इस सदन में और उस सदन में कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन बिलकुल ऐसा है जो न एग्रीकल्चर के बारे में जाने न एग्रीकल्चरल प्राइसेज के बारे में जाने, उसे कोई जानकारी नहीं है, कुछ टेक्नीशियंस बैठ कर उभोक्ता के नाम पर कह दिया, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, जो 75 परसेंट लोगों का सेक्शन है, उसको मारता है। क्या रिलेशनशिप है, क्या वर्किंग की गई है, मुझे बताया जाय कि हर चीज की खास तौर से दो तीन साल से कीमते बढ़ती जा रही हैं। अभी माननीय जैन साहब ने उसे प्वाइंट आउट किया। मैं उसके अलावा बताना चाहता हूँ, क्या यह बात सही नहीं है कि इरिगेशन रेट्स सवाए हो गए कम से कम इन तीन वर्षों में और फर्टिलाइजर्स की इस कटौती में जितनी हाई

[श्री एस० डी० मिश्र]

प्राइसेज हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं, न एशिया में है, न यूरोप में है, न अमेरिकन कंट्रीज में है। जब इनपुट्स की प्राइसेज इस तरह से बढ़ती हो तो कौन सा आंकड़ा है, किस बेसिस पर एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने इसको प्रोक्वोरमेंट प्राइस रखा और र्यूमनेरेटिव प्राइस कह कर मजाक उड़ाया। जब र्यूमनेरेटिव प्राइस कहते हैं तो मजाक सा लगता है। मजाक करते हैं। यह मिनिमम प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, अनर्यूमनेरेटिव प्राइस है। क्या है? यह कह कर कि उपभोक्ता को राहत दी जायगी तो उपभोक्ता को राहत देने की चाहे जो और स्कीम लाइयेँ, सबसिडि लाइये, क्यों किसानों के प्रति इतने उदासीन हैं। मैं यह वार्निंग देना चाहता हूँ, आज यह आन्दोलन केवल पंजाब का नहीं है, इसको आप समझ लें, इस पर देश में गरीब किसान, अमीर किसान, मध्यम किसान सब का है, सब हाई-इलिङ्ग वैराइटी का काम कर रहे हैं तो सब के पास कुछ कपडे के लिये और सामान के लिए बचता है, कोई छोटा किसान एक एकड़ का है, वह भी कुछ उसको बचा कर कपड़ा लेना चाहता है और और काम करना चाहता है। तो उसको कम्प्यूजन में न लाइये कि बड़े किसानों की समस्या है, यह तमाम देश के किसानों की समस्या है, यह केवल पंजाब के किसानों की समस्या नहीं है। पूरे देश की है, महाराष्ट्र की है, सबकी समस्या है, तो अगर इस पर सरकार उदासीन हो और सोचे कि इलेक्शन हो गया, चार वर्ष ठीक है कि रहेंगे" . .

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) :
आप समाप्त कीजिये।

श्री एस० डी० मिश्र : मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ।

आप इस तरह से न सोचें कि अगर आपका बहुमत भारी हो गया है तो किसानों को पददलित कर दें तो आप समझ लें कि राइटिंग्स आन दि वाल आपके सामने हैं, इस पर आप विचार करें और सोचें। हमें यह बताएं कि इसको क्यों आप र्यूमनेरेटिव प्राइस कहते हैं, इसको मिनिमम प्राइस नहीं बल्कि र्यूमनेरेटिव प्राइस कैसे कहते हैं। हर चीज का दाम बढ़ा है, सारे इनपुट्स का दाम बढ़ा हुआ है तो कौन से आंकड़े प्राइसेज कमीशन के हैं, जिसने आपको इम्प्रेंस किया है। आप बराबर टाईद कर रहे हैं, कहते हैं उन्होंने सब किया है, वह किताब में है। कितनी एविडेंस हैं, मेन एविडेंस है, हमको दीजिए, कोई जनरल जवाब न दीजिये, फलों चीज में कमी हुई है, प्राइसेज गिरती जा रही हैं, यह बताइये। ऐसी स्थिति में आप स्पेसिफिक आसर मेहरबानी करके दीजिये, जिससे कि हमको और देश को संतोष हो।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

So far as the question raised by the hon. Member is concerned, I have already given the reply that this is the opinion of the Commission. They have taken into consideration the various factors which have been mentioned by the hon. Member and after taking those factors into consideration they still think that the prices which they have suggested would be remunerative enough to the cultivator. That is the view expressed by the Agricultural Prices Commission. But the Government have not yet come to any decision whether the recommendation is acceptable or not acceptable. That decision will be taken by the Government later on.

Now, it is true that prices have increased. . .

(Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : लेकिन कब होगा जब किसान का परचेज खत्म हो जायगा ।

SHRI MAN SINGH VARMA (Uttar Pradesh) : Are you satisfied with the recommendation ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : The Government have already issued instructions that so far as the present purchase price is concerned, it should be at the existing level. I think in some places the purchases are being made. With regard to the future prices, that will be decided soon after the Chief Ministers' Conference.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): May I know whether the Government in the Ministry of Agriculture has got a cell to assess the cost of production of the various agricultural products ? I want a very specific reply to this. Also I would like to know whether any attempt has been made to work out the cost of production of wheat and, if so, whether that cost of production is above or below the cost of production worked out by the Agriculture Price Commission. Have they got any cell to determine the cost of production ? I want a very specific reply in this matter.

Secondly, I want to know whether the Government is having the buffer stock organisation to help the farmer or the consumer because out of the subsidy of Rs. 120 crores about Rs. 57 crores is going for interest, and that means it has got nothing to do with the price given to the wheat growers. I want to know whether this is a fact or not.

The next point is, as has been rightly pointed out the value of the rupee in 1967 when these prices were fixed was higher than it today is and you are allowing the rise in the cost of production in the industry. You have got a Cost Accounts Bureau and you have the

Tariff Commission also. Everywhere industrial products have risen by 15 to 50 per cent and the Government has been in favour of rise in price but when the question of farmers comes, the Government is always led by bodies like the Agriculture Price Commission which has no experts at all.

The last point I want to know is whether, as a long-term perspective, the Government will evolve a new policy of popularising heat consumption because the production of wheat has increased by 10 per cent and consumption is lagging by 3.5 per cent. Unless this is done the problem will not be solved.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : It is true that at present there is no organisation which exists so far as the assessment of cost of production is concerned. But we have set up in our Ministry a cell for the purpose of finding out the data and I think in above two years time it will be possible for us to say definitely what the cost of production is.

SHRI A. G. KULKARNI : I want to know whether assessment for the present wheat prices has been made by your cell.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Not by our cell. But we have set up a cell.

So far as the present prices are concerned, we take into consideration the facts ascertained by the agricultural universities and by the Statistical Departments of the various State Governments. We take those facts into consideration and I think the Agriculture Price Commission has already taken that fact into consideration.

So far as the difference in the price is concerned, I think it is not Rs. 120 crores. The subsidy will be about Rs. 132 crores or Rs. 133 crores out of which Rs. 52

[Shri Fakhruddin Ali Ahmed]
crores or Rs. 53 crores will be in respect of interest and other charges for buffer stocks. That is a fact.

SHRI A. G. KULKARNI : What has the farmer to do with it ?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : It is all right. Shri Sanyal.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) : Of late, large number of educated unemployed people have become agriculture-minded. The doors of traditional employment are now closed to them and they have made a little investment in buying small farms and costly manure and bringing them under cultivation in the expectation that they will get a good return. Now, at the very outset to bring down the prices of wheat is to put a chilling effect upon their ardent enthusiasm. Therefore, may I ask the hon. Minister if it is possible for the Government, as a common ground, free from all controversy, free from all statistical problems, to give some subsidy to the producer so that he can get a remunerative price ? The subsidy may vary from State to State, from district to district, from place to place. There should be some sort of subsidy to the producer so that he will get a remunerative price if you keep up the price level and if that hits the consumer, you can also introduce another kind of subsidy, namely, at the consumer's point. If you introduce these two point of subsidy, then there will be balanced economy between production and consumption and also maintenance of a fair price. One would be remunerative for the grower and the other would be accommodating for the consumer. If there is a surplus after that, you can keep it for next year which may be a lean year also or you should try to explore avenues for exporting such wheat to other countries which need it. Is it

possible for the Government to sit down and work out this formula ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

The same question is being repeated from time to time. I have already said that all these are taken into consideration by the Commission and their recommendation is before us and we shall examine it before we take our decision regarding this matter.

SHRI D. D. PURI (Haryana) :

Do Government still remember that not very many year ago this country was living from ship to mouth ? Are they completely oblivious to the fact that again not very long ago grain trains had to be diverted while on the rails because the grain stocks in some cities had gone down below dangerous levels. Do Government consider the timing of the recent announcement of price as fair ? The grower has grown the wheat and the wheat is to come to the market and all of a sudden the price being reduced. Do the Government consider that fair ? Can the Government mention any commodity, agricultural or non-agricultural, the price of which is below what it was last year ? Arising out of this is a very interesting exercise that has been posed by Mr. Jain. Will the Government apply their mind :

(i) To the depleted purchasing power of the rupees.

(ii) And take into account the increased cost for the inputs and then work out what in real terms is the amount by which the price is being reduced ?

Lastly having regard to the turmoil that these recommendations have caused all over the country and having regard also to the unanimity of views expressed in the consultative committee, will the Government declare that this recommendation of the commission is not worthy of their consideration ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: These are suggestions which will be taken into consideration.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): There are demonstrations in Punjab—it is reported in the press to day—against the recommendations of the Agricultural Prices Commission. I would like to know whether the attention of the Government has been drawn to the statement issued by the CPI in Punjab in which it is pointed out how the peasant is going to be adversely affected if the recommendations were to be accepted and the prices lowered? Now the Government says they have not accepted this recommendation. It is good. How are they going to settle this matter. The Minister said that when the Chief Ministers come he would discuss with them at the Chief Minister Conference. Surely the CMS are not experts necessarily. Some of them may know a little more than others but surely they could not be taken as experts

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अब तो टेलीफोन पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं ।

SHRI BHUPESH GUPTA : They should be consulted, I am not opposed to such consultation but what about consulting the representatives of the toiling peasantry—the working peasantry? They should be consulted. There are certain organisations of the peasantry and their representatives could be called and their opinions sought over this matter because it is very important. First of all, only the other day we discussed in this House the sufferings of the cotton growers and now the wheat growers are in danger of suffering. In view of this I would like to know what mechanism Government is going to set up for consultation before a final decision by the Government is taken on this matter. Do I have an assurance that the representatives of the peasants' organisations, agricultural labourers' organisations and others will be consulted before the

decision is taken and also, if possible, the parties here should also be consulted.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : The matter has already been considered by the Consultative Committee. There is the Farmers' Forum in Parliament and they have also expressed their views. We shall also know the views of the Chief Ministers and their reaction as far as the recommendations of the Agricultural Prices Commission are concerned. After taking all these facts into consideration Government will take a decision.

SHRI BHUPESH GUPTA : What is the harm in consulting the representatives of the peasants' organisations in the country? We know the Consultative Committee is there. We ourselves are here and we express our opinions here. But you are not taking the decision here straightway; you must be consulting people who are in close touch with the peasants; I would not bother to which party they belonged or they do not belong.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Their views have been expressed both in the press and outside and that will also be taken into consideration.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : I am glad that the Minister is not yet committed to accept the recommendations of the Commission and he was good enough to say that a final decision will be taken after giving due regard to the views expressed here in this House and in the other House as well. The Consultative Committee has already met and they have expressed their views. But one thing I just want to emphasize here. There is no doubt that the Government has a majority and the people's mandate is with them. But it is not as if you can do anything you like. It should not be taken for granted that whatever the Government does they do as representatives of the people. Actually speaking in a parliamentary system whatever is the majority of the Government party, they represent the governors

[Shri Mahavir Tyagi]

and the opposition, whether it is big or small, represents the governed. We members of the Opposition are the real representatives of the people as far as the relationship between the governed and the governors is concerned. Therefore whenever the interests of the people are involved it is our responsibility to safeguard their rights and it is in this context I might just say with regard to this talk about subsidy that whatever be the the subsidy it is not a matter of charity. Subsidy is money collected from the people and it goes to the people themselves. It is not Government's money. It is their own money and it goes for an important matter. So it is not a question of ordinary charity; it is a matter of living for the poor people. For their day to day living they have to have subsidy. How could the poor people live without subsidy? Subsidy is no matter of generosity on the part of the Government; subsidy is the right of the people. As far as the prices of wheat and other agricultural products are concerned I must tell the hon. Minister that the members of this House as well as of the other House are practically unanimous that the prices should not be reduced. I could understand if you had said this before the election. After the elections are over you come and say that the prices will be reduced, but the elections will come again. As far as we in the Opposition are concerned, as true representatives of the people I declare here and now that if the prices of foodgrains are reduced in this manner we in the Opposition will all unite together and consider the feasibility of starting a mass civil disobedience campaign to refuse to give grain and let us see what happens. This is a challenge.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

So far as the first contention is concerned that only members of the Opposition are representatives of the people, I dispute that. Not only the members of the Opposition but members who support the Treasury Benches are also true representa-

tives of the people and they have in unequivocal terms expressed their views in regard to this matter which is not different from the views of the Opposition. All these will be taken into consideration.

डा० माई महावीर (दिल्ली) : श्रीमन्, मैं मंत्री जी से एक बात यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, जो इकोनामिक सर्वे की रिपोर्ट इस साल सदन के पटल पर रखी गयी थी, उसके अन्दर भी सरकार ने जो अन्न की हैडलिंग करने और स्टोक करने का खर्चा है वह 13 रुपये 60 पैसे क्विंटल से बढ़ कर 15 रुपये हो जायगा यह कहा है और अगर सरकारी गेहूँ को रखने का खर्चा बढ़ रहा है तो क्या सरकार के ध्यान में जो कास्ट किसान के सामने आती है जिस पर उसके टूल्स का, फर्टिलाइजर का, ट्रैक्टर आदि का सारा खर्च भी पड़ता है और पिछले वर्ष में और इस वर्ष के बजट के बाद खास तौर पर ट्रैक्टरों की कीमत बढ़ाने के बाद वह और भी ज्यादा बढ़ गया है तो अगर सरकार का हैडलिंग करने का खर्चा बढ़ रहा है और जैसा कि सर्वेक्षण में कहा गया था कि उस के बजाय बढ़ने की संभावना है, तो मैं जानना चाहूँगा मंत्री जी से कि उस खर्च के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए क्या किसानों के बढ़े हुए खर्चों को ध्यान में रखने की जरूरत सरकार को नहीं प्रतीत होती और इसलिए जब 120 करोड़ से घटा कर सब्सीडी 100 करोड़ की गयी तो सरकार ने एक तरह से मारेली एग्रीकल्चर कमीशन की इस सिफारिश को बिलकुल ही स्वीकार नहीं कर लिया है कि यह प्रोबयोरमेंट प्राइसेज को कम करने जा रहे हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिकली यह है कि जब मंत्री जी कहते हैं कि हम सारी चीजों का विचार कर फैसला करेंगे, तो अपनी सब्सीडी की रकम को 120 करोड़ जो होना चाहिए थी,

आपके अपने कहने के मुताबिक, उसको 100 करोड़ तक ला कर क्या एक तरह से आपने स्वीकृति नहीं दे दी कि आप एग्रीकल्चर कमीशन की इस सिफारिश को मानेंगे ? और दूसरा नुक्ता जो मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि समाचार पत्रों में जो लुधियाना का समाचार छपा है कि वहाँ किसानों ने माग की है कि जो हमने कर्ज लिया है, उस कर्ज को रुपये की शक्ल में लेने के बजाय उनसे जिन्स की शक्ल में, काइन्ड के रूप में उनसे वसूल किया जाय और उन्होंने एक तरह से सरकार को कहा है कि अगर वह हमारा गेहूँ वसूली के एवज में नहीं लिया जा सके तो खास तारीख के बाद जो गेहूँ पड़ा रह जायगा, उसके खराब होने की ओर नष्ट होने की जिम्मेवारी सरकार की होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या इस बात की खबर सरकार के सामन आयी है और इसके बारे में मंत्री जी का क्या कहना है।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

Sir, it is not correct to say that the cost of procurement is Rs. 13 per quintal. The cost of procurement is about Rs. 11 per quintal, the cost of distribution is about Rs. 7 per quintal and the cost on account of interest and other charges for the buffer stock is about Rs. 3 per quintal. All this comes to Rs. 26 per quintal. It is true that we have to examine whether the cost of procurement and the cost of distribution can be reduced to some extent. I am examining to what extent it is possible, and to the extent possible, we shall do so.

DR. BHAI MAHAVIR : Because there seems to be some confusion, for the Minister's kind attention I will read this from the Economic Survey.

"As for 1972-73, the cost of procurement of wheat is likely to remain unchanged at Rs. 11 per quintal, but the cost of distribution and that of carrying over of the buffer is expected

to increase marginally from Rs. 13.60 to Rs. 15 per quintal. With the total cost of procurement and distribution at around Rs. 26 per quintal, and the procurement price remaining unchanged," etc

I am referring to the cost of distribution and that of carrying over of the buffer, and am saying that the cost of carrying over of the buffer is going to increase from Rs. 13.60 to Rs. 15. So, that is increasing.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED :

The hon. Member has taken the two figures together and I have given them separately. What has appeared in the papers is true and we have seen in the press reports about the discontent of the farmers, so far as the farmers are concerned, this has been expressed in the newspapers I have already said that this problem is before us and we shall take into consideration what are the remunerative prices and whether the procurement price of wheat will have to be increased in future. After taking that factor into consideration, Government will reach a decision. It is also true that the producers require incentive, and that incentive we have to give as far as possibly we can.

DR. BHAI MAHAVIR : The costs are increasing. The cost of inputs is increasing and Government's cost of handling is increasing.

SHRI MAHAVIR FYAGI : The Minister seems to be quite sympathetic.

DR. BHAI MAHAVIR : What I ask for is that there is to be some parity between the two, between the cost of inputs and the return which he gets. So also Government's cost of handling is increasing. The farmer's cost has also increased. Will the Government not take this into account ? And how do they explain the reduction of the subsidy from Rs. 120 crores to Rs. 100 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) Well, you have made your suggestions to the Minister.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : No suggestion has been accepted. I do not know wherefrom the hon Member gets the idea of reducing the subsidy from Rs. 120 crores to Rs. 100 crores. If the present price is maintained, both the procurement price and the issue price, the subsidy will be in the neighbourhood of Rs. 132 crores.

SHRI T N SINGH (Uttar Pradesh) : In the matter of prices being fixed for industrial goods, the Tariff Commission is given certain terms of reference and instructions about costing return on capital, interest, etc. I want to know, when the question of price fixation is referred to the Agricultural Prices Commission, whether the Government gives instructions to the Agricultural Prices Commission on the lines of the Tariff Commission in regard to the return on the capital invested, remuneration to labour, etc., so far as foodgrains are concerned. That is point No 1. Secondly, has the Government noted that the handling charges come to more than thirty per cent of the price when the foodgrain reaches the consumer? Is this handling charge not much more than what it used to be when there was no rationing or control in this country? The regular trade managed it much cheaper. I think I am right and I can say with authority on the subject. Thirdly, ever since the idea of the Agricultural Prices Commission was mooted in 1961 when I was a Member of the Planning Commission, a suggestion was made by us that there should be a principle for return on capital in fixing prices and the Government resisted that. Why is this being resisted even today? Is that principle acceptable or not, viz., so far as the agriculturist is concerned he should have a return on the capital invested and the labour employed?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : So far as the last question is concerned,

there are no figures before the Government on the basis of which a return on the capital can be ascertained or assessed.

SHRI T N SINGH : You give instructions to the Tariff Commission.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : As I have already pointed out, we have set up a cell in our Ministry to collect data. I hope that in a year or two or in three years' time it will be possible for us to get data when we will be able to fix these things.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) Last question, a very short one. Three Members have already spoken from your side.

DR. V. B. SINGH (Uttar Pradesh) : Maybe thirty Members have spoken, but what I am going to say is not repetition. What are the criteria based on which prices are to be determined? I can conceive that the political element is an element to the price determination and that is what is happening here Sir, let us try to see that when the word 'farmer' is used, the farmer is not a monolithic category. There are big farmers, medium farmers and small farmers. So far as the gains from higher prices of agricultural commodities are concerned all the three do not benefit in the same manner. The small farmer, in some months of the year, has to purchase foodgrains. Once the price of agricultural commodities are higher, they may enter the cost of production of industrial goods which distort the cost structure in general and the farmers are not to gain ultimately when they purchase industrial commodities. Therefore, to the extent there are demonstrations from the farmers, I can understand that they have a reason because their income is being eroded due to the recommendation of the Agricultural Prices Commission. But there is no counter demonstration by the consumers to balance the situation.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) : Please ask for some clarification on the point made by the Minister.

DR. V. B. SINGH : It is not a question of giving clarification. It is one of giving information.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Not necessary.

SHRI SHYAM LAL YADAV : He has already employed experts.

DR. V. B. SINGH : The point that I want to stress is that the Agricultural Prices Commission has taken into account the fact that the prices of inputs have gone up but the index of agricultural productivity has gone higher. Therefore, the income to the farmer, after taking into account the higher cost of production, is more than in previous years. Therefore it is a very rational proposition that the prices of procurement should be lower, and in this way the consumers can also benefit and the farmers can benefit because of higher output, and not because of higher prices.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : That is the argument advanced by the Agricultural Prices Commission.

[Shri J. P. Yadav rose]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Two members have already spoken for your party. अच्छा, छोटा सा सवाल पूछिए ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं छोटा ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पी०एल० 480 से जो गेहूँ मंगाते थे, उस गेहूँ के नहीं मगाने से कितने रुपये की बचत हुई और जो किसानों ने इस बचत में सहयोग दिया, उसके लिए आपने क्या किया। अब की बार आपके बजट में जो फिगर्स दिए गए उसके अनुसार ट्रैक्टर्स के दाम, खाद के दाम और खेती के काम आने वाले औजारों के दाम, सभी बढ़ गये हैं और छोटा किसान जब बीज खरीदने जाता है तो उसको उसके लिए भी बढ़े हुए दाम देने पड़ते हैं। जब

इस तरह से खेती के काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ते हैं तो यह प्राइस फिक्स करके कैसे गेहूँ के दाम घटा सकते हैं ?

श्रीमन्, जब जैन साहब बोल रहे थे तो मैंने कई बार उठ कर प्रश्न करना चाहा कि यह जो कृषि मूल्य निर्धारण आयोग बने हैं उसमें बैठे महानुभावों के नाम क्या हैं, उनका कृषि से क्या सम्बन्ध है, उनकी योग्यता क्या है ताकि उनका नाम यह सदन और हमारा देश जाने और किसानों को भी जानकारी मिले जो इस मूल्य में कमी करने के लिए सरकार के खिलाफ आन्दोलन करेगी। मुझे यह पता है कि आप कृषि आयोग किसके लिए बनाए थे। यह कृषि आयोग किसानों के लिए नहीं बल्कि जो उस समय चुनाव टार गये थे उनको अध्यक्ष बनाने के लिए चाल थी और जब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो एक वर्ष तक वह अध्यक्ष का पद खाली रहा और हमने लिखा-पढ़ी की कि आपने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। तो एक वर्ष तक आपने आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया। ऐसे हारे हुए लोगों को सुविधा देने के लिए कृषि मूल्य निर्धारण आयोग का गठन किया गया है।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : It is not correct, Sir.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, जवाब तो दिया नहीं।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT (1970-71) OF THE
CARDAMOM BOARD

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF FOREIGN TRADE
(SHRI A. C. GORGE) : Sir, I beg to lay
on the Table a copy (in English and Hindi)